बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 321323 पटना, दिनांक:- 11/08/17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0-115-01/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना ।
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।
सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
आयुक्त स्वरोजगार-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका), ग्रा0वि0वि0, बिहार ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं में तीव्र गति से प्रगति एवं परिणाम लाने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अ0स0 पत्र संख्या- Secy(RD)/Misc/2017 दिनांक-07.04.17

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, बिहार को संबोधित संलग्न प्रासंगिक पत्र के द्वारा वर्ष 2019 तक पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1 (एक) करोड़ आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की आवास की समस्या का समाधान के साथ ही इन परिवारों को निम्नांकित योजनाओं से लाभान्वित कराने के संबंध में कार्य किया जाना है :-

(1) लाभुकों के निवास स्थान तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क की सुविधा ।

(2) मनरेगा के तहत जल संरक्षण (वर्ष 2019 तक 50,000 सूखा ग्रस्त ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण देने का लक्ष्य) ।

(3) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं नि:शक्त व्यक्तियों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुँचाने हेतु लाभुकों की सहमति से बैंक खाता को AADHAR से जोड़ने की कार्रवाई ताकि लाभुकों को सहायता राशि प्राप्त करने के लिए Banking Correspondents, Postal Banks and PDS के माध्यम से Bio-metric readers एवं POS machines द्वारा उनके घर पर ही पेंशन की व्यवस्था उपलब्ध हो सके ।

(4) दीन दयाल अंत्योदय योजना ।

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के साथ-साथ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जीविका उपलब्ध कराना ।

इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन कार्यक्रमों के लक्ष्य को पूरा करने हेतु केन्द्रांश की निधि में बढ़ोतरी की गई है तथा ससमय केन्द्रांश की निधि की विमुक्ति हेतु ससमय राज्यांश की विमुक्ति एवं अंकेक्षित लेखा समर्पित करने की अपेक्षा भी की गयी है ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 के लिए 6,25,625 आवासों का कार्यान्वयन कराया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 5,38,989 आवासों का औपबंधिक भौतिक लक्ष्य संसूचित है ।

अत: ग्रामीण विकास की योजनाओं में तीव्र गति से प्रगति एवं परिणाम लाने हेतु प्रासंगिक पत्र की प्रति अग्रेतर कार्वाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/11/17

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 321323 पटना, दिनांक 11/08/17

प्रतिलिपि- (अनुलग्नक सहित), मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- (अनुलग्नक सहित), सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/11/17

सरकार के सचिव

अमरजीत सिन्हा
AMARJEET SINHA

सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 011-23382408
E-mail: secyrd@nic.in

DO # Secy(RD)/Misc./2017

April 7, 2017

Subject: **Department of Rural Development Programmes 2017-18**

Dear Chief Secretary,

At the outset I want to thank you for the support and guidance for Rural Development Programmes. All our programmes have done well in 2016-17. Your constant review has guided the Rural Development Department of your State.

2. I am happy to inform you that we have already approved all the programmes for all the Divisions for 2017-18 and detailed record of proceedings and approvals have been communicated to all the States. We have ambitious targets to ensure completion of 1 crore Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) houses by 2019 and to connect all eligible habitations with all weather road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) by 2019. We would like you to review the preparedness of the concerned Departments as there is no constraint of financial resources at our end. The State share for these programmes may also be provided on time. Funds under all our programmes are being released immediately to ensure that work begin with full speed.

3. Funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) are also being released in the next 2-3 days. April to June is a period of high demand for work. Through Mission Water Consevation Guidelines, we have focussed on 2,261 Blocks in the country which are dark or grey Blocks and which are irrigation deficient. Water Conservation is our top most priority under MGNREGS and I would request you to review at your level to ensure that such works are taken up with appropriate technical and scientific scrutiny as per need. Our target is to drought proof 50,000 Gram Panchayats through Water Conservation measures by 2019. Please also review timely wage payments under MGNREGS. We want to ensure that delayed payments are less than 10% in 2017-18.

4. While the work of digitisation under the Nationa Social Assistance Programme (NSAP) for pensions to old, widows and disabled has been completed, I would like to urge a review at your level to give a push to Aadhaar linked accounts with consent, for pensions. With a larger number of Banking Correspondents, Postal Banks and PDS shops with bio-metric readers and POS machines, Aadhaar linked accounts can facilitate availability of pension at the doorstep.

contd...

154

5. The Deen Dayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) along with Skills Programme is an effective intervention for women's empowerment and livelihood diversification. Building capacities and improving Bank linkage can speed up the pace of livelihood diversification considerably. A review at your level will facilitate the process.

6. Financial allocations for all our programmes have been considerably increased and are adequate to meet the requirements to fulfil our targets. Timely release of State share and timely submission of audited accounts and other General Financial Rules (GFR) requirements will facilitate timely release of Central shares. I seek your continued guidance and support to move effectively in improving the outcomes of the programmes of the Department of Rural Development.

With regards,

Yours sincerely,

[Amarjeet Sinha]

7 April 2017

Shri Anjani Kumar Singh
Chief Secretary
Government of Bihar
Patna - 800 001